कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

# मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–36, अंक – 3 | फरवरी 1–15, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–6

## सी.ई.एल. के मज़दूरों ने निजीकरण के ख़िलाफ़ अपना संघर्ष और तेज़ किया

केंद्र सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सी.ई.एल.) के निजीकरण पर फिलहाल के लिये रोक लगा दी है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव, जिनको निजीकरण की प्रक्रिया की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है, उनके अनुसार सी.ई.एल. में 100 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी को नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग के हाथों बेचने के लिए, सरकार की ओर से आशयपत्र (एल.ओ.आई.) अभी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार सी.ई.एल. के निजीकरण पर कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच–पड़ताल कर रही है।

27 अक्तूबर, 2016 को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने सी.ई.एल. की बिक्री प्रक्रिया शुरू की थी। सी.ई.एल. को बेचने के लिए अब तक दो कोशिशें हो चुकी हैं। पहली कोशिश में छह बोलियां प्राप्त हुई थीं, लेकिन कोई वित्तीय बोली नहीं प्राप्त हुई। दूसरी कोशिश को फरवरी 2020 में शुरू किया गया। इस बार दो कंपनियों ने अक्तूबर 2021 में वित्तीय बोली पेश की। नवंबर 2021 में नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग ने सी.ई.एल. को ख़रीदने के लिए 212 करोड़ रुपये की पेशकश की, उसको सबसे अधिक बोली लगाने वाले ख़रीदार के रूप में चुना गया। सरकार ने मार्च 2022 तक सी.ई.एल. को बेचने की प्रक्रिया को पूरा करने की योजना बनाई थी।

सी.ई.एल. के मज़दूर एकजुट होकर निजीकरण का सख़्त विरोध करते आ रहे हैं। सी.ई.एल. की साहिबाबाद स्थित फैक्ट्री के कर्मचारियों की यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा पिछले चार महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। निजीकरण का विरोध करने के लिए, पार्टी संबद्धता को तोड़ते हुए, सभी यूनियनें

एक साथ मिलकर एक संयुक्त बैनर तले संघर्ष कर रही हैं। सभी यूनियनें मिलकर निजीकरण के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को दिल्ली उच्च न्यायालय तक ले गई हैं। दिसंबर 2021 में, ट्रेड यूनियनों ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के समक्ष बोली लगाने की और बिक्री की प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। ख़बर है कि अब सी.ए.जी. बोली लगाने की और बिक्री की प्रक्रिया की जांच कर रही है।

नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन (एन.सी.ओ.ए.) और नेशनल फोरम ऑफ एक्जिक्यूटिव्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने सी.ई.एल. को बेचने के फ़ैसले की कड़ी निंदा की है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की प्रयोगशालाओं के पूर्व निदेशकों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भी सरकार से सी.ई.एल. के निजीकरण के फ़ैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। एक बयान में उन्होंने अन्य मुद्दों के साथ इस हक़ीक़त को भी उजागर किया है कि नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग के पास न तो कोई अचल संपत्ति है, न ही कोई ज़मीन या भवन है और इस कंपनी के एक भी कर्मचारी ने अभी तक पांच साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है।

सी.ई.एल. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1974 में देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करने के उद्देश्य से की गई थी। सी.ई.एल. मुख्यतः चार व्यवसायों में काम करती है, क) रेलवे सुरक्षा और सिग्नलिंग सिस्टम; ख) रक्षा–संबंधित (रणनीतिक) इलेक्ट्रॉनिक्स; ग) सौर फोटोवोल्टिक और घ) सुरक्षा निगरानी से जुड़े उपाय और साधन। इस सार्वजनिक क्षेत्र के इस उद्यम ने देश में पहली बार अपने स्वयं के अनुसंधान और विकास प्रयासों के साथ–साथ, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) व रक्षा अनुसंधान एवम विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) जैसी कई सरकारी प्रयोगशालाओं के सहयोग से कई सफल उत्पाद विकसित किए हैं। सी.ई.एल. बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में अग्रणी है। सी.ई.एल. ने देश की सुरक्षा से संबंधित उत्पादों के लिए कई महत्वपूर्ण पुर्जों को भी विकसित किया है और देश के सशस्त्र बलों के लिए इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है। यह संस्थान अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने वाली कंपनी है। इसके बावजूद, सरकार सी.ई.एल. को एक निजी कंपनी को बेचने पर तुली हुई है, वो भी एक ऐसी कंपनी को जिसके पास सी.ई.एल. की किसी भी तकनीक का कोई अनुभव नहीं है।

नंदल एक वित्त कंपनी है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। वित्तिय कंपनियां, ऐसी कंपनियों को सस्ते में ख़रीद कर, किसी भी तरह तुरंत मुनाफ़ा कमाने और ख़रीदी हुई कंपनी को कुछ वर्षों के बाद किसी अन्य देशी या विदेशी पूंजीपति को बहुत अधिक क़ीमत पर बेचने का धंधा करने के लिए जानी जाती हैं।

सी.ई.एल. के कर्मचारियों ने बताया कि यह एक मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी है, जिसके पास इस समय 1500 करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन में हैं। और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा 132 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान किया जाना। इसके अलावा, सी.ई.एल. के पास दिल्ली–एन.सी.आर. में 50 एकड़ ज़मीन है, जिसकी क़ीमत आज की तारीख में 500 करोड़ रुपये से भी अधिक है।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने किसी भी क़ीमत पर सी.ई.एल. को बेचने का प्रयास किया है। जब पहली बार

शेष पृष्ठ 6 पर

## किसान आंदोलन – वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा

*मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित पांचवीं सभा*

11 जनवरी, 2022 को मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) ने 'किसान आंदोलन – वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा' विषय पर पांचवीं सभा आयोजित की।

सभा में मुख्य वक्ता थे डा. दर्शनपाल, क्रांतिकारी किसान यूनियन, पंजाब। क्रांतिकारी किसान यूनियन, पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) का एक संस्थापक सदस्य है। इस मोर्चे में 500 से अधिक किसान संगठन शामिल हैं और यह देशभर के किसानों के संघर्ष को अगुवाई दे रहा है। एक महीने पहले, 11 दिसंबर, 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सरहदों पर अपने सालभर के आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। एस.के.एम. ने यह फैसला तब लिया था जब तीनों किसान–विरोधी कानून, जो 2020 में ससंद में पास किये गये थे, वापस लिये गये और केन्द्र सरकार ने किसानों की बाकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिया।

बिरजू नायक ने एम.ई.सी. की ओर से सभा का संचालन किया। उन्होंने क्रांतिकारी किसान यूनियन, पंजाब के काम का संक्षेप परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने डा. दर्शनपाल को सभा को संबोधित करने का आह्वान किया। डा. दर्शनपाल के भाषण के बाद एम.ई.सी. की ओर से संतोष कुमार ने अपना वक्तव्य पेश किया। उसके बाद बहुत ही उत्साहपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें देश के अलग–अलग इलाकों से तथा ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया से अनेक कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन की आगे की दिशा पर अपने विचार दिये।

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित इस सभा में डा. दर्शनपाल की प्रस्तुति को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं।

शेष पृष्ठ 2 पर

### अंदर पढ़ें


- डा. दर्शनपाल, क्रांतिकारी किसान यूनियन, पंजाब की प्रस्तुति 2
- बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में चंडीगढ़ के बिजली कर्मियों का संघर्ष 3
- आंध्र प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगें मनवाईं 5

# डा. दर्शनपाल, क्रांतिकारी किसान यूनियन, पंजाब की प्रस्तुति

साथियों,

किसान आन्दोलन आज किस परिस्थिति में है और इसका भविष्य क्या है? – यही है आज की मीटिंग का अजेंडा।

आज की परिस्थिति क्या है? मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आन्दोलन ने पिछले साल 2020 से लेकर 2021 तक जो एक माहौल बनाया था, उस लम्बे आन्दोलन के चलते ऐसा लगने लगा था कि शायद यह आन्दोलन अपने देश में कोई राजनीतिक बदलाव की तरफ ले जायेगा। क्योंकि इसमें केवल किसान ही नहीं, किसानों के अलावा, बाकी तबके के लोग थे। उनमें भी एक इस तरह की फिलिंग आ रही थी या आन्दोलन करने की जिज्ञासा उठ रही थी और उठी भी। ऐसा लगने लगा कि देश में एक बड़े जन आन्दोलन का उभार बन सकता है।

लेकिन हुआ यह कि मोदी जी ने अचानक 19 नवंबर को तीन कानून वापस लिए और आन्दोलन को एक तरह से सस्पेंड करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। बाकी मुद्दों पर भी बीजेपी/एनडीए की सरकार ने हमसे कुछ वादे किए और हम ने 11 दिसंबर को आंदोलन को स्थगित किया।

उसके बाद की परिस्थिति में जाने से पहले, मैं सबसे पहले वहां से शुरू करूंगा, जो आन्दोलन की वास्तविकता है। आन्दोलन को उन सब मुद्दों को उठाना पड़ा, जिन मुद्दों पर किसानों ने कभी नहीं सोचा था, जैसे कि सीधे कारपोरेट के साथ संघर्ष में जायेंगे, या सीधे केन्द्र सरकार के साथ इस तरह का टकराव होगा। जो इस आन्दोलन में हुआ।

इसके बारे में, मैं बहुत पहले, बहुत जगहों पर अपनी बातें रख भी चुका हूं। आज भी यहां रखने की कोशिश करूंगा। क्या–क्या ख़ासियतें इस आन्दोलन में थीं, जबसे आन्दोलन शुरू हुआ, 11 दिसंबर तक। आन्दोलन में क्या–क्या चीजें थीं, जो इस आन्दोलन को इस तरह का बना पाईं। वह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो भी आन्दोलन होने हैं, उन्हें इन सब चीजों का ज़रूर ध्यान रखना होगा, उसके तर्जुबे से, सबकों सीखकर, उनको अपने आंदोलनों में जोड़ना होगा।

किसान आन्दोलन का विश्लेषण करने के लिये, हमें यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 किसान शहीद हुए। उस शहादत के बाद भारत के किसान संगठनों में एक साथ आने की एक आकांक्षा उठी। 6 जून (2017– संपादक) को मंदसौर की घटना हुई। मुझे लगता है कि 13 या 14 जून को एक बड़ी मीटिंग गांधी पीस फाऊंडेशन दिल्ली में हुई। मैं पहले भी किसान संगठनों की बैठकों में जाता रहता था। लेकिन पहली बार, मैं देखता हूं कि विभिन्न विचार, राजनीति, विश्वास वाले किसान संगठनों के नेता उस मीटिंग में एक मंच पर आए थे। उस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में दो मुद्दों को लेकर सहमति हुई। किसान की संपूर्ण कर्ज़ मुक्ति और एम.एस.पी. की गारंटी इन दोनों मुद्दों को लेकर किसानों को एकताबद्ध करने का फ़ैसला हो गया। इस मीटिंग में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (ए.आई.के.एस.सी.सी.) बनी। उसके बाद इसी मंच से पूरे देश में यात्राएं निकली, दिल्ली में किसान संसद लगी। दिल्ली में बड़ी–बड़ी रैलियां भी हुईं। दो–ढाई साल तक यह प्रक्रिया चली। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 मार्च, 2020 को देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लॉकडाउन के दौरान भी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से कुछ न कुछ गतिविधि जारी रही।

4 जून (2020 संपादक) को खेती के तीन कानून का अध्यादेश आया। उन अध्यादेशों के मुद्दे को पंजाब के संगठनों ने गंभीरतापूर्वक नहीं उठाया। इस मुद्दे को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में पंजाब के संगठनों ने उठाया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय भी सामूहिक समझ और नेतृत्व थी। मुझे यह याद है कि जिस दिन ये तीन अध्यादेश आए, व्यक्तिगत तौर पर मैंने तुरंत उन तीन अध्यादेशों के मूलपाठ को बैंगलोर में अपने एक साथी के पास भेजा, जो ए.आई.के.एस.सी.सी. की वर्किंग ग्रुप मेम्बर थीं। तत्काल उसके साथ पूरी चर्चा की और हमने उन अध्यादेशों का खुलासा पंजाब में करना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया पंजाब में थोड़ी ज्यादा सक्रियता, तेज़ी और व्यापकता से चली। यह उसकी ख़ास विशेषता है। क्योंकि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने फ़ैसला करके दो–तीन तरह का बुलावा दिया था कि पहला, प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। दूसरा, पंजाब में, पूरे देश में एन.डी.ए. सहयोगियों के घरों या उनके दफ़्तरों के सामने धरना करेंगे। यह बुलावा हमने बार–बार दिया था। उसकी व्यवहारिक लामबंदी थी। उन दिनों की मीडिया में आप देखेंगे कि पंजाब में लामबंदी फिजिकल हो रही थी। बाकी प्रांतों में कोरोना– लॉकडाउन की वजह से बहुत ही प्रतीकात्मक/टोकन भागीदारी होती थी। लेकिन पंजाब में काफी बड़े पैमाने पर लामबंदी हो रही थी। मैं एक घटना बताना चाहता हूं। पंजाब के 10 संगठन, ऑफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पंजाब चैप्टर ने अपनी तरफ से स्वतंत्र बुलावा भी दिया। हमने बुलावा दिया कि पंजाब के सभी जिलों में, एन.डी.ए. सहयोगियों के दफ्तरों और घरों के सामने एक डिमांड चार्टर लेकर किसान जायेंगे। इस चार्टर को हम लोगों ने बनाया था। इसकी गाइड लाइन्स अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से आयी थी, जिसको पंजाब में उसको पूरा लागू किया गया। शायद जुलाई महीने के अंत से अगस्त के पहले हफ्ते तक, पंजाब में ट्रैक्टर मार्च हुआ।

पहली बार हमने महसूस किया कि ट्रैक्टर मार्च में पंजाब का नौजवान आ रहा है जो मार्च में 65–75 फीसद है। पहले किसान संगठनों में बुजुर्ग 50–55 वर्ष के ऊपर के लोग आते थे। ये नौजवान ट्रैक्टर मार्च में बहुत ही ऊंचे स्वर में गाने लगाकर बहुत ही तेज स्पीड में ट्रैक्टर को चलाकर शहरों में मार्च करते हुए, बीजेपी और अकाली दल के प्रतिनिधियों के घरों की तरफ गए। ऐसा दुबारा किया गया, फिर बड़े पैमाने पर नौजवान आये। पंजाब में यह जो आंदोलन बना, इसमें पंजाब के नौजवानों द्वारा इतना दबाव बढ़ गया कि पंजाब की अकाली दल, जो एन.डी.ए. की सहयोगी थी उसे एन.डी.ए. से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा। उसकी एकमात्र सेंट्रल मिनिस्टर हरसिमरत कौर को मिनिस्टरी छोड़नी पड़ी। मैं कहना यह चाहता हूं कि पंजाब की पूरी सोसाइटी जिसमें नौजवान, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल, उनके साथ आ मिले, जो पूरे किसान आन्दोलन के साथ तीन क़ानून और बाकी मुद्दे उठा रहे थे। यह सब अगस्त के महीने तक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं।

पूरे पंजाब में आन्दोलन में 10 किसान संगठनों के अलावा और भी संगठन थे। सभी किसान संगठनों ने आपस में बैठकर, मिलकर काम करने का फ़ैसला किया और 28 संगठनों का एक मोर्चा बन गया।

इस मोर्चे की ओर से 25 सितम्बर (2020 संपादक) को पंजाब बंद का बुलावा दिया गया। यह बंद पूरी तरह से सफल रहा, आप कह सकते हैं कि एक परिंदा भी सड़क पर नहीं था। पूरे पंजाब में नौजवान अपनी गाड़ियां लेकर, कार लेकर, मोटरसाईकल लेकर, जीप लेकर जश्न मनाते हुए घूम रहे थे बंद को सफल बनाने के लिए।

ट्रैक्टर मार्च के दिन और बंद वाले दिन ऐसा लग रहा था कि पंजाब, दिल्ली के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। इस माहौल में पंजाब के और किसान संगठन भी आ मिले। उन्होंने प्लान किया कि अब इसकी दिशा को केंद्र सरकार की तरफ मोड़ा जाए। उस दिशा के लिये बी.के.यू. एकता उगराहां और किसान मजदूर संघर्ष समिति ने बोल दिया कि हम भी आपके साथ (वो पंजाब किसान संगठनों के साथ शामिल नहीं हुए बाहर से समर्थन दे रहे थे) हैं। और बाकी संगठनों का एक मोर्चा बनाया गया और जो भी छोटे–छोटे संगठन बाहर थे, उनका भी यह संदेश आया कि आप जो फ़ैसला लेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। फिर शुरू होता है वह जंग जो सीधे दिल्ली के साथ।

फिर क्या था, पहला, पूरे पंजाब में सभी रेलवे ट्रैकों को जाम कर दिया। दूसरा, पूरे पंजाब के टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया। तीसरा, फ़ैसला लिया गया कि पंजाब में अडानी और अंबानी के जो भी उत्पाद और सर्विस थे, उनका बायकाट कर दिया जाये, उनके पेट्रोल पंप को सीज किया जाए, उनके माल्स के सामने धरना लगाकर बैठा जाये। अकाली दल बीजेपी से उस समय अलग हो चुका था। पहले हम घोषणा कर चुके थे कि बीजेपी और अकाली दल के लोग गांव में आयेंगे तो हम गांव में घुसने नहीं देंगे। उसी डर की वजह से और दबाव के चलते अकाली दल एनडीए से बाहर आ चुका था। इसके बाद बीजेपी के जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके दफ्तरों और घरों के सामने धरने लगाकर बैठ गये। मैं इसे चार पॉइंट पैकेज कहूंगा। बीजेपी का विरोध, टोल प्लाजा को फ्री कर देना, रेल ट्रैक को बंद करना और पेट्रोल पंप, माल्स को बंद करना। इसके बारे में अख़बारों ने भी लिखा है। बाद में यह स्थापित हुआ, जिसे हम पंजाब मॉडल ऑफ स्ट्रगल कह सकते हैं। यह मॉडल काफी क़ामयाब हुआ। पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों हिल गए। शायद 19 अक्तूबर (2020 संपादक) का दिन था। कैसे पंजाब सरकार ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पास किया, जिसमें हर पार्टी के विधायकों ने जुलूस के रूप में राज्यपाल को प्रस्ताव देकर आए जिसमें दो बीजेपी विधायक को छोड़कर बाकी सभी विधायक एक साथ थे। मतलब सब राजनीतिक पार्टियां किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाने को मजबूर हो गई थीं। जिसमें पंजाब की सरकार भी शामिल थी।

इस दबाव में आकर केन्द्र सरकार ने 8 तारीख को हमें बैठक में आने का न्यौता दिया। हमारी बातचीत चली तो एस.एस. अग्रवाल कृषि सचिव ने कहा कि हम आपको समझायेंगे–बुझायेंगे, क्या क़ानून है, कैसे किसानों के पक्ष में है, आप आइए बैठिए, अगर आप चाहोगे तो हम मंत्री जी से मिला देंगे। हम पंजाब के संगठनों ने मीटिंग करके तय किया और उनको जवाब दे दिया कि हम आपकी मीटिंग में नहीं आयेंगे। हमने उस मीटिंग का बॉयकाट किया। रेल ट्रैक पर जाम जारी रहा। पूरा संघर्ष चल रहा था। बीजेपी के लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। फिर से केन्द्र सरकार ने 14 अक्तूबर को दिल्ली बुलाकर बोला कि हम कृषि मंत्री से भी मिलवायेंगे। हम यहां से गए। बाकायदा मीटिंग रखी गई लेकिन जैसे ही हम ऑफिस में घुसे, सचिव एस.एस. अग्रवाल ने परिचय देना शुरू किया। हमने बोला कि मंत्री जी कहां हैं? वे बहानेबाजी करने लगे। हमने बोला कि आपके एक मंत्री पंजाब में गए हुए हैं और दूसरे आप बोल रहे हैं कि दूसरी मीटिंग में हैं और प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं। हमने उनको अपनी बात सुनाई और उस मीटिंग का बायकाट करके चले आए। उस बायकाट को लेकर पूरी दिल्ली की प्रेस मीडिया में आ गया कि पंजाब के किसान मीटिंग का बायकाट करके चले गए। यह अक्तूबर के महीने की बात है, जो अगस्त के महीने में पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद चीजें केन्द्र सरकार के साथ आगे बढ़ती है। फिर दूसरी मीटिंग भी फेल कर जाती है, जो तीन मंत्रियों के साथ होती है।

इससे पहले, मैं फिर आपको याद कराना चाहता हूं कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 26 और 27 नवबंर को 'दिल्ली चलो' का बुलावा दिया था। उधर पंजाब के संगठन पंजाब में संघर्ष कर रहे थे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के उस फ़ैसले को मैंने उस समय कार्यकारी समूह सदस्य के बतौर, पंजाब के किसान संगठनों को बताया और दिल्ली में 26 अक्तूबर की मीटिंग के लिए आमंत्रित किया, जिसमें देशभर से किसान संगठनों को बुलाया गया। उस मीटिंग में और 27 अक्तूबर को जो दूसरे दिन मीटिंग चली, उसमें सभी किसान संगठन, पंजाब के सभी किसान संगठन, दक्षिण भारत के किसान संगठन शामिल हुए, इसमें बीकेयू के राकेश टिकैत नहीं थे।

उस मीटिंग में तय हो गया कि 26–27 नवम्बर को, जो आंदोलन है, उसको केवल ए.आई.के.एस.सी.सी. नहीं बल्कि पूरे देश के बाकी किसान संगठन भी एक साथ लड़ेंगे। उसके लिये पांच लोगों की कमेटी भी बना दी गई। अभी कुछ संगठन थे, वे उस मोर्चे में नहीं आये, उस समय तक भी बीकेयू एकता उगराहां एक ओबजरवर थे, उस समय भी वे मोर्चा में शामिल नहीं हुये। लेकिन उसके बाद हमने एक और चांस लिया। पंजाब में आंदोलन चल रहा है, 7 नवम्बर को दिल्ली के गुरूद्वारा रकाबगंज में एक और बड़े संगठनों की मीटिंग होती है। वहां फाइनल किया जाता

शेष पृष्ठ 4 पर

# बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में चंडीगढ़ के बिजली कर्मियों का संघर्ष

11 जनवरी, 2022 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बिजली विभाग के मज़दूरों ने यू.टी. पावरमैन यूनियन के बैनर तले चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण का विरोध करने के लिए एक विशाल रैली और प्रदर्शन किया। उन्होंने वेतनमान में संशोधन को लागू करने और कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी करने की भी मांग की। पदों की उपलब्धता और पात्रता के बावजूद इन आदेशों को रोक दिया गया था।

रैली के दौरान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल के साथ–साथ चंडीगढ़ के प्रशासन को ज्ञापन देकर, बिजली वितरण के प्रस्तावित निजीकरण को वापस लेने की मांग की। उन्होंने सभी जन संगठनों और राजनीतिक दलों से अपील की कि वे बिजली मज़दूरों के संघर्ष का समर्थन करें और निजीकरण की नीति का कड़ा विरोध करें। लोगों को बिजली कर्मियों के समर्थन में लामबंध करने के लिए एक व्यापक जन संपर्क अभियान की योजना बनाई जा रही है, जिसके ज़रिये लोगों को अवगत कराया जायेगा कि यदि विभिन्न क्षेत्रों और जन उपयोगी सेवाओं का निजीकरण किया गया तो इससे उनके हितों को कितना नुक़सान होगा। केंद्र सरकार के इस क़दम का केंद्र शासित प्रदेश की सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों ने पहले ही विरोध किया है।

मई 2020 में कोविड महामारी के बीच वित्त मंत्री ने एकतरफा घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा। चंडीगढ़, जहां केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग की विद्युत शाखा संचारण, वितरण और खुदरा आपूर्ति की सेवा कर रही है, जिसका निजीकरण करने के लिए पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया था। इस प्रस्ताव को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि विद्युत अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस तरह की निजीकरण प्रक्रिया की अनुमति देता हो। उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया कि विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल भी शुरू नहीं की जा सकती, ख़ासकर तब, जब वह मुनाफ़े में चल रही हो। 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री अन्यायपूर्ण और अवैध है क्योंकि विभाग पिछले तीन वर्षों से मुनाफ़ा कमा रहा है। यह आर्थिक रूप से कुशल है, विद्युत मंत्रालय द्वारा संचारण और वितरण में निर्धारित घाटे के 15 प्रतिशत की सीमा से भी कम नुक़सान का उसका रिकॉर्ड है। न्यायालय ने 1 दिसंबर, 2020 को निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए, इसे "अन्यायपूर्ण और अवैध" घोषित कर दिया था। हालांकि 12 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने उस स्थगन को ख़ारिज़ कर दिया और निजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी। प्रशासन द्वारा प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के बाद, यू.टी. पॉवरमैन यूनियन ने फिर से उच्च अदालत में एक याचिका दायर की, अदालत ने 28 मई, 2021 को इस प्रक्रिया पर रोक लगाने का फ़ैसला सुनाया लेकिन 28 जून, 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आदेश पर फिर रोक

लगा दी गई। निविदा प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है।

इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने गोयनका समूह की कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कार्पोरेशन (सी.ई.एस.सी.) की सहायक कंपनी, एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की 871 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी है। सी.ई.एस.सी. कोलकाता में निजी एकाधिकार वाली एक बिजली वितरक कंपनी है, जो वहां पर देश की बिजली की सबसे ऊंची दरों पर बिजली वितरित करती है। केंद्र सरकार ने केवल 174 करोड़ रुपये का मामूली आरक्षित मूल्य तय किया है, जबकि लोगों के धन से वर्षों में बनाए गए इसके बुनियादी ढांचे का वास्तविक मूल्य लगभग 20,000 करोड़ रुपये माना जाता है। इसके

अलावा, विद्युत मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की संपत्ति, जिसके लिए परिसंपत्ति रजिस्टर में लागत का कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है, इसको एक रुपये की मामूली लागत पर निजी कंपनी को हस्तांतरित किया जा सकता है।

इस बीच पूरी प्रक्रिया के लिए सलाहकार नियुक्त की गई कंपनी डेलॉइट, इस विभाग को कंपनी में बदलने की योजना बना रही है। इसके बाद, शेयर समझौते सहित अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और बनाई गई नई कंपनी के शेयरों को निजी कंपनी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस केंद्र शासित प्रदेश में बिजली संचारण और वितरण का नुक़सान 10 प्रतिशत से कम है और यह एक बहुत ही लाभदायक सरकारी उपक्रम है। इसने पिछले वित्तीय वर्ष में 365 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और देश में सबसे कम बिजली दर रखने वाले उपक्रमों में से एक होने के बावजूद, यह लगातार लाभदायक रहा है। बताया जा रहा कि इतनी बड़ी संपत्ति के लिए मूल्य तो केवल तीन साल से कम समय में मुनाफ़े के साथ वसूल किया जा सकता है!

सरकार यह तर्क देती है कि वह केवल घाटे में चल रही इकाइयों को ही बेच रही है, यह तर्क स्पष्ट रूप से झूठा है। कोई भी निजी कंपनी कुछ भी ऐसा ख़रीदने के बारे में सोच नहीं सकती, जो भूमि और उपकरण जैसी संपत्ति प्राप्त करके अपने मुनाफ़े या संभावित लाभ को कई गुणा न बढ़ा पाए! चंडीगढ़ के लोगों को डर है कि निजीकरण के बाद जल्द ही चंडीगढ़ में बिजली की दरें कम से कम दोगुनी हो जाएंगी।

11 जनवरी को हुई जनसभा में यूनियन ने सर्वसम्मति से सभी शिफ्टों में 1 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल और 23–24 फरवरी, 2022 को दो दिवसीय हड़ताल करने का निर्णय लिया है।

सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि अगर प्रशासन कर्मचारियों के हितों की रक्षा किये बिना, बताए हुए समय से पहले ही कारोबार सौंप देने का निश्चय करता है, तो तत्काल अनिश्चितकालीन हड़ताल की जायेगी और उस स्थिति में हड़ताल के कारण आम जनता को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।

यू.टी. पॉवरमैन यूनियन के आह्वान पर 24 जनवरी को चंडीगढ़ में एक और जनसभा का आयोजन किया गया। लगातार कई दिनों तक कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव सहित यू.टी. पॉवरमैन यूनियन के कई नेताओं ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि निजीकरण के क़दमों को आगे बढ़ाने में सरकार और प्रशासन की जिद को देखते हुए, जैसा कि पहले तय किया गया था कि मज़दूरों के पास 1 फरवरी और 7 फरवरी को हड़ताल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और 23–24 फरवरी को अखिल भारतीय आम हड़ताल में भी भाग लेने को कहा।

पांडिचेरी के यूनाइटेड फोरम ऑफ एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स ने भी चंडीगढ़ के हड़ताली बिजली कर्मचारियों के समर्थन में एकजुटता हड़ताल का संकल्प लिया। चंडीगढ़ बिजली कर्मचारियों के संघर्ष को तब और भी ताक़त मिली जब एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. (नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईम्प्लाईज़ एंड इंजीनियर्स) ने फ़ैसला लिया कि वे 1 फरवरी को बड़े पैमाने पर चंडीगढ़ के साथ–साथ पांडिचेरी के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के साथ एकजुटता में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। सभी राज्यों से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. की ओर से एक ज्ञापन भेजा जाएगा। नेशनल फेडरेशनों के मुख्य नेता चंडीगढ़ में प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे आस–पास के इलाकों से लोग जुड़ेंगे। इसी तरह का आयोजन पांडिचेरी में भी होगा।

सीटू चंडीगढ़, फेडरेशन ऑफ यू.टी. एम्प्लाइज़ यूनियन, हॉर्टिकल्चर यूनियन, आई.सी.सी.डब्ल्यू., पंजाब बोर्ड कॉर्पोरेशन फेडरेशन के नेताओं ने बिजली कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और लोगों व उपभोक्ताओं पर निजीकरण के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया।

आज बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसे सभी को किफ़ायती दर पर उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। बिजली को इजारेदार पूंजीपतियों के लिए अत्याधिक मुनाफ़े का स्रोत नहीं बनने दिया जा सकता। राज्य को निजी मुनाफ़े के लिए लोगों के धन से बनी संपत्ति को बेचने का भी अधिकार नहीं है।

बिजली क्षेत्र के मज़दूर पिछले एक साल से निजीकरण के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के साथ–साथ जम्मू–कश्मीर में भी हड़ताल करके मज़दूरों ने अपनी मांगों को जीता है। अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों की बारी है कि वे निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष को आगे बढ़ाएं।

http://hindi.cgpi.org/21795

**Mazdoor Ekta Lehar (Internet Editions)**

Hindi: http://www.hindi.cgpi.org, English: http://www.cgpi.org

Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org & Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com

Ph.09868811998, 09810167911

## डा. दर्शनपाल, की प्रस्तुति

पृष्ठ 2 का शेष

है कि 26–27 नवम्बर का, जो हमने एक साथ आने का फ़ैसला किया है, पूरे देश में, केवल पंजाब के संगठन नहीं, पूरे देश के संगठन आ रहे हैं। 7 लोगों की कमेटी बन जाती है। इसका नाम संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) दिया जाता है। 7 नवम्बर, 7 लोगों की कमेटी, जिसमें देश के पूरे संगठन शामिल हैं। राकेश टिकैत साहब इसमें शामिल नहीं थे। उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन शामिल नहीं थे। पंजाब के दो संगठन इसमें शामिल नहीं हैं – बीकेयू एकता उगराहां और किसान मजदूर संघर्ष समिति (पंजाब)। लेकिन बाकी देश के किसान संगठन उसमें आ गए।

तो फिर शुरू होती है, अगली तैयारी, ख़ासकर पंजाब से। एक हद तक हरियाणा से शुरू होता है। पंजाब के किसान संगठनों का 14 नवम्बर, 2020 को रेलवे मंत्री, कृषि मंत्री और हमारे पंजाब के एक मिनिस्टर से बातचीत फेल हो जाती है। देखिये, उस दिन के बारे में, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 14 नवम्बर, 2020 को अगर केन्द्र सरकार थोड़ी सी भी लचीली होती तो हमारा एक समझौता हो जाना था। पंजाब के किसान संगठन तैयार थे। लेकिन रेलवे मिनिस्टर इतने जिद्दी थे कि उन्होंने पंजाब के संगठनों की इस बात को भी नहीं माना कि जो गुड्स ट्रेन हैं, उसको अलाउ कर देते हैं, पैसेंजर ट्रेन को नहीं। हमने दोनों ट्रेन को रोका हुआ था। लेकिन पंजाब में उन दिनों गेहूं की बुवाई का सीजन चरम पर था। खाद की ज़रूरत थी, बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की ज़रूरत थी, डीजल की ज़रूरत थी। उधर सरकार शोर मचा रही थी कि जम्मू में मिलट्री की बहुत सारी सप्लाई रुकी हुई है। लेकिन हम जिद पर थे कि गुड्स ट्रेन तो चलाओ पंजाब के लिये, लेकिन हम पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने देंगे। लेकिन वह मंत्री जिद्दी था, बातचीत टूट गयी।

उसके बाद तैयारी शुरू होती है दिल्ली मार्च की। तो पंजाब में, मैं फिर यह दोहरा दूं कि पंजाब के सब राजनीतिक दल, पंजाब के सब धार्मिक संगठन, पूरे पंजाब की धार्मिक शख़्शियतें – ये सब आंदोलन के पक्ष में आ गए। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले ट्रैक्टर मार्च के बाद, पंजाब के नौजवान और सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ गयीं, उनसे जुड़े नौजवान भी किसान आंदोलन के पक्ष में आ गए। पूरे पंजाब में आंदोलन की जो आग थी, उसमें किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ने के लिए अंगडाई ले रहे थे। दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिये, किसानों ने हर घर में ट्रैक्टर को सजा लिया। ट्रोली को घर बना लिया, म्यूजिक सिस्टम लगा लिया। किसानों ने बड़े पैमाने पर तैयारी की, उसमें ख़ासकर नौजवानों का हिस्सा ज्यादा था। पंजाब के नौजवानों को जो हौसला मिल रहा था, वह थी युनिटी ऑफ़ द पीपल ऑफ़ द पंजाब। ख़ासकर उसमें भी मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब का जो बैग्राउंड सिख, धार्मिक इतिहास बलिदान का है, सिखों का योगदान पूरे समाज को है। मुगलों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। बस्तीवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है। उसमें जो योगदान पंजाबियों ने और खासकर जो सिखों ने दिया है, वह भी एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा था। पंजाब के लोगों की लड़ाई दिल्ली के साथ थी। दिल्ली उनको औरंगजेब लगता है, दिल्ली उनको ब्रिटिश लगता है, दिल्ली उनको पंजाबियों का दुश्मन जैसा लगता है। यह एहसास था लोगों में और इसमें हर एक आत्मिक, रूहानी, शारीरिक, संगठनात्मक, राजनीतिक, हर प्रकार की जो ऊर्जा थी, शक्ति थी, वह इकट्ठी, एक साथ आ गयी थी।

26 नवम्बर से पहले, जब हमने पंजाब के किसान संगठनों की मीटिंग की थी और संयुक्त किसान मोर्चा की जिस दिन स्थापना हुई थी (7 नवम्बर, 2020, संपादक), उस दिन किसान संगठनों का यहां तक कहना था कि हमें दिल्ली जाना है, पर दिल्ली में हमें घुसने नहीं देंगे। और दिल्ली के बाहर जहां भी हमें रोका जायेगा, वहां हम बैठेंगे और वहीं हम धरना देंगे, दो दिन, तीन दिन अगर ट्रैफिक रुकेगा, फिर तय करेंगे। 7 लोगों की कमेटी बनायी गयी, जो बाकी संगठनों के साथ सलाह–मशवरा करके आगे क्या करना, उसका फ़ैसला करेगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 26 नवम्बर को जो ऊर्जा, ताक़त, पंजाब के लोगों में आयी, उस दिन हरियाणा–पंजाब के बार्डर पर कोई चार या पांच जगह बैरिकेड लगे हुये थे। किसान संगठन के नेताओं का फ़ैसला था कि बैरिकेड पर रोका जायेगा तो रुखकर वहीं बड़े पंडाल लगा लिया जायें, वहीं बड़ी रैली कर दी जाये, वहीं सड़क को रोक लिया जाये। लेकिन जिस सोच से पंजाब के लोग आए थे, ख़ासकर नौजवान, उनकी ऐतिहासिक दुश्मनी दिल्ली से थी, उनको लग रहा था कि हमें दिल्ली जाना है।

मैं खुद का अनुभव बताता हूं, कि अगर उस दिन कोई भी किसान नेता, वह थोड़ा सा भी विरोध करता या नौजवानों को रोकता, तो किसान नौजवान, उनके ख़िलाफ़ हो जाते। लेकिन किसान संगठनों के नेताओं ने दूर दृष्टि दिखाई। 26 नवंबर को और 27 नवंबर को केवल पंजाब नहीं बल्कि मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि पूरा देश, पूरी दुनिया ने पंजाब के लोगों, सिखों के इस रिहरसल को रियल में होते देख रहे थे। दिल्ली की तरफ मार्च हो रहा था। पूरी दुनिया में, न्यूयॉर्क से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, बैंगलोर से, बोम्बे से, कलकत्ता से, हर जगह से, टीवी और मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे थे। देख ही नहीं रहे थे, चिंतित थे, चिंतित ही नहीं थे, वे उनके साथ थे। जैसे ही ट्रैक्टरों ने यात्रा शुरू की, ये पूरी दुनिया के लोग, उनके साथ–साथ दिल्ली के बॉर्डर तक चले। दो रात और 1 दिन की यात्रा करके पंजाब के किसान और लोग जैसे ही टिकरी बॉर्डर और सिंघु बॉर्डर पर पहुंचे तो उसके साथ–साथ अन्य संस्थाएं, धार्मिक शख़्सियतें, हमारे लंगरों के लोग, पानी देने वाले लोग, कपड़े देने वाले लोग, दवाई देने वाले लोग, साथ–साथ वहां आए। उन्हें ऐसा लगा कि केवल किसान नहीं पूरा पंजाबी समाज आया है। एक तरह का ऐसे लगने लगा कि कोसमोपोलिटन सोसाइटी है जो दिल्ली के बाहर आकर बैठ गई है। उधर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने रोकने का बहुत ही यत्न किया। आंसू गैस के गोले छोड़े। पानी की बौछारें की। सड़क पर बड़ी–बड़ी 10–10 फुट 15–25 फुट गहरी खाइयां खोद डालीं, बड़े–बड़े पत्थरों से रास्ते रोके गए। हर चीज को रोकते हुए, खाइयों को मिट्टी से पाटते हुए, ट्रैक्टर निकले, सभी गाड़ियां निकलीं। वहां बैठने के बाद भी सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, किसान आंदोलन के ख़िलाफ़ बहुत तरह की साजिशें रची गयीं। नेताओं को बहुत तरह के विशेषणों से नवाजा – कभी बोला ये खालिस्तानी हैं, ये तो अलगाववादी हैं, ये तो माओवादी हैं, ये फला हैं, बहुत कुछ बोला गया। लेकिन सरकार ने और भी कोशिश की कि कहीं इनको रोक कर दिल्ली के अंदर एक बड़ा ग्राउंड तक का रास्ता दे दें। उन्होंने बड़ा पैकेज दिया कि आपको रास्ता दे देते हैं। एक खुला ग्राउंड है बुराड़ी ग्राउंड वहां जाकर बैठ जाओ। अधिकांश किसान संगठनों ने इस प्रस्ताव को खारिज़ कर दिया, वहीं बॉर्डर पर बैठने का ही फ़ैसला किया। उस आंदोलन के दो बड़े सेंटर – सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर थे। वहां पंजाब से ही लोग गए थे। पर गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, ये तीन बॉर्डर जहां ब्लॉकेड हुआ, वहां भी पंजाबियों की कंट्रीब्यूशन काफी बड़ी थी। उदाहरण के रूप में, गाजीपुर बॉर्डर में भी टिकैत जी, रोड के हाईवे के नीचे थे। वहां धरना लगाकर 100 के क़रीब किसानों के साथ बैठे थे। लेकिन उस हाईवे को दिल्ली में जाने से ब्लॉक किया तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई एरिया से आए हुए विस्थापित पंजाबी किसानों ने। राजस्थान बॉर्डर पर भी सबसे पहले, सबसे ज्यादा गिनती में जो लोग आए, वह भी हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसान, जो विस्थापित पंजाबी बैकग्राउंड के थे।

मैं कहना यह चाहता हूं कि पूरी दुनिया में देश और पंजाब का किसान केन्द्र में था। पंजाबी लोग और सिख लोग उसकी धुरी थे। देश में एक ताक़त और ऊर्जा इस तरह से बन गई थी, जिसके चेत और अचेत मन में था कि हम लड़ाई लड़ने चले हैं दिल्ली के साथ। यही कारण है कि इस तरह के मुहावरे बहुत जल्दी बन गए – दिल्ली बॉर्डर पर या हम जीत के जाएंगे या हमारी लाश जाएगी, क़ानून वापसी या घर वापसी। एक तरह से किसानों की प्रतीज्ञा थी कि कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट को नहीं घुसने देंगे, दिल्ली सरकार यानी केन्द्र सरकार को यह सब लागू नहीं करने देंगे, हम किसान को उसका एम.एस.पी. दिलवा कर रहेंगे। किसानों की यही प्रतीज्ञा (कमिटमेंट) किसान नेताओं की प्रतीज्ञा में दृढ़ता लाने वाली चीज थी। उसमें आम लोगों का किसान संगठनों के साथ आ मिलना भी था।

किसान आंदोलन बॉर्डर पर बैठा तो 1 साल में हम देखते हैं कि उस आंदोलन का सिंघु बॉर्डर पर एक ऐसा केन्द्र बन गया, जहां से पूरे देश में एक आवाज़ जाने लगी। शुरू में जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था, वह बाल्यवस्था में था। बॉर्डर पर वह जवान हुआ और प्रौढ़ता के साथ आगे बढ़ा। इसकी लगातार यहां मीटिंग हुई। फ़ैसले होने लगे। सरकार के साथ मीटिंग फेल हुई। 22 जनवरी (2021 संपादक) के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद पूरे किसान आंदोलन का प्रतीक सिंघु बॉर्डर और एस.के.एम., यानी संयुक्त किसान मोर्चा, बन गए। संयुक्त किसान मोर्चे में जितने भी संगठन थे, वे देश के अपने–अपने प्रांतों में संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर लेकर सीधा आंदोलन में उतरे। टिकरी बॉर्डर या सिंघु बॉर्डर के साथ सॉलिडेरिटी में नहीं, बल्कि आंदोलन में सीधी भागीदारी की।

मैं फिर से यह बात दोहराना चाहता हूं कि आंदोलन में पंजाब के मज़दूरों, महिलाओं, दलितों, नौजवानों, छात्रों, कर्मचारियों, हर तबके ने योगदान दिया है। हर एक धार्मिक संस्थान ने, खासकर गुरूद्वारों ने, वह चाहे एस.जी.पी.सी, यानी शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ थी या नहीं थी, सभी ने इस आंदोलन में योगदान दिया है। किसानों के मुद्दों के लिए किसानों की अगुवाई में यह आंदोलन सर्वव्यापी बन गया। इस आंदोलन ने पहली बार कारपोरेट के ख़िलाफ़, उसका बायकाट करके यह बताया कि कारपोरेट कैसे दुश्मन है। इस आंदोलन ने मोदी जी के फासीवाद को चुनौती दी। पहली बार सीएए, एनआरसी, कश्मीर में इन्होंने जो किया या इस तरह के जो काम करके सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की, अपना केन्द्रीय क़ानून बनाने की कोशिश की, इस आंदोलन ने उसे चुनौती दी और उसे रोका। वे चाहते तो इस आंदोलन को भी बिखेर सकते थे, लेकिन उनकी कोई हिम्मत नहीं हुई। उसके बहुत सारे कारण हैं, विस्तार में हम नहीं जाएंगे।

यह बात सही है कि इस आंदोलन ने किसानों को एकजुट किया है। किसानों के मुद्दों को फोकस किया है। किसानों के साथ–साथ पूरे देश के लोगों को एकजुट किया है। देश में बीजेपी के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी, वह बढ़ने लगी। जो पंजाब से होती हुई हरियाणा में, हरियाणा से होती हुई यूपी में, और पूरे देश में फैल रही थी। यही आज उत्तर प्रदेश में प्री–इलेक्शन फेज़ में हम देख रहे हैं। पंजाब में मोदी जी का काफिला रुकने के रूप में दिख रहा है। मुझे लगता है कि एंटी–बीजेपी

शेष पृष्ठ 5 पर


**किसान आन्दोलन के सामने कुछ सवाल**

**हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के साथ साक्षात्कार**

**हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध**
**(कीमत 25 रू. और डाक खर्च 20 रू.)**

निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी, नई दिल्ली, खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :- ई-392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस-2, नई दिल्ली - 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

# आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगें मनवाई

आंध्रप्रदेश राज्य के हजारों कर्मचारियों ने शनिवार, 5 फरवरी 2022 को आंदोलन करके अपनी कुछ मांगें मनवा लीं। आंदोलन का नेतृत्व पे रिवीजन कमीशन स्ट्रगल कमेटी कर रही थी और आंदोलित कर्मचारियों में शिक्षक भी शामिल थे।

राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के बीच लंबी बातचीत के बाद 5 फरवरी के दिन के अंत तक हड़ताल वापस ली गयी। 4 फरवरी को कर्मचारियों ने हाल में घोषित वेतन संशोधन के ख़िलाफ़ विजयवाड़ा शहर की सड़कों पर जुलूस निकाले थे और धमकी दी थी कि रविवार मध्य रात्रि से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे।

सरकार ने कर्मचारियों की हाऊस रेंट अलाउंस (एच.आर.ए.) और सिटि कंपनसेटरी अलाउंस, जो वेतन आयोग के आदेश के अनुसार बंद हो गये थे, उन्हें वापस लौटाया। इसके साथ–साथ कुछ अन्य सुविधाओं को वापस बहाल किया गया है। सरकार ने यह भी माना कि 1 जुलाई, 2019 से 30 मार्च, 2020 के बीच, दी गयी अंतरिम राहत में तत्काल वह कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगी। सरकार ने यह भी माना कि हर दस साल की जगह, हर पांच साल में वेतन संशोधन किया जायेगा।

17 जनवरी को घोषित वेतन संशोधन की वजह से कर्मचारियों के वेतन में कटौती की संभावना थी। यह मुद्दा अभी तक संतोषजनक तौर पर सुलझाया नहीं गया है।

http://hindi.cgpi.org/21810

## डा. दर्शनपाल, की प्रस्तुति

पृष्ठ 4 का शेष

की यह वेव किसी न किसी रूप में जारी है। और इसका स्रोत, शुरुआत किसान आंदोलन थी। किसान आंदोलन में बीजेपी की कोशिश थी कि मुसलमानों और जाटों को और गुर्जरों को, मीणा को फाड़ के रखा जाए। उसको जवाब दिया गया। जब हम दिल्ली में गए, उसके बाद, लोग हमें बोलने लगे कि मोदी मुर्दाबाद के नारे मत लगाना प्लीज, यह नारे मत लगाना। लेकिन आंदोलन के चलते–चलते, यह सब एकदम तोड़ दिया, मरोड़ दिया। अमित शाह और मोदी के राज को देखने से लगता था कि शायद आंदोलन को किसी न किसी तरीक़े से तोड़ देंगे। लेकिन यह भी संभव नहीं था। क्योंकि पंजाब में आंदोलन मैदान पर था। ऊपर से, पंजाब एक सीमा राज्य है। यहां सिख बहुसंख्यक हैं। सिख हिन्दोस्तान में अल्पसंख्यक हैं। पंजाब की सीमा कश्मीर के साथ भी लगी हुई है। इस डर से भाजपा सरकार रुक गयी कि अगर हम यहां पर दमन करेंगे, तो उसके बाद, मोदी जी की सरकार को और बहुत कुछ चुकाना पड़ता। वह न दमन कर सकते थे, न ही तीन क़ानून को वापस लेने वाले थे, क्योंकि कारपोरेट का दबाव था। लेकिन अंततः उनको 19 नवंबर को बहाना बनाते हुए तीन क़ानूनों को वापस लेना पड़ा।

मुझे लगता है कि इस आंदोलन ने भारतवर्ष के लोगों के लिए कुछ रास्ते बनाए हैं। कुछ पगडंडियां बनाई हैं। किसान आंदोलन की वजह से, अपने आप में पहली बार ऐसा लगने लगा है कि देश में किसान अगर एकजुट हो जाते हैं, एक बैनर के नीचे साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह बाकी वर्गों की तरह ही है, जैसे मजदूर वर्ग, जितने भी ट्रेड यूनियन में हमारे साथी हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन में हैं या और छोटे–छोटे ट्रेड यूनियन में हैं, अगर वे मिलकर लड़ सकते हैं, तो किसान भी मिलकर एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। मुझे यहां तक लगता है कि किसानों की पहचान (आइडेंटिटी) और एकता (यूनिटी), बनाने के लिए देश में सकारात्मक और अनुकूल परिस्थिति हैं। यह बनाई जा सकती है और बनेगी, अगर हमारी डिफरेंट फोर्सेज, जो किसानों में काम करती हैं, इसके लिए वे गंभीरतापूर्वक काम करें तो। दूसरा, इसके साथ–साथ अगर देश की वर्किंग क्लास के ट्रेड यूनियन, जो संगठित क्षेत्र में हैं, वे भी इसी तरह इकट्ठे हो जाते हैं, तो देश में एक बड़ा यूनाइटेड फ्रंट बनाकर देश में बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पंजाब में जब 10 संगठन से 28 संगठन हुए, तो आंदोलन एक ऊंची पीक पर गया। 25 सितम्बर के बंद के रूप में देखने में आया। जब पंजाब के संगठनों के साथ, देश के अन्य संगठन मिल गए और सब संगठनों ने मिलकर कॉल दिया 26 नवम्बर को दिल्ली चलो का, यह तभी हो पाया है क्योंकि देश के संगठन एक साथ थे। उसके साथ पंजाब की जो एकता थी, जो पंजाबियों की बन चुकी थी। ये सारे तथ्य हमें बताते हैं, कि अगर देश में आंदोलन करने हैं, देश में तानाशाही या फिर केन्द्रीयकृत शासन (सेंट्रलाइज्ड रूल) के खिलाफ़ लड़ाई लड़नी है, तो अवाम के बड़े तबके, किसान और मज़दूर, इनमें जो भी विचारधारा, राजनीतिक, संगठनात्मक मतभेद के चलते, छोटे–छोटे समूह या छोटे या बड़े, उन सबको किसी न किसी तरह से अपना एक संयुक्त कार्यक्रम बनाकर, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर, सबको एक साथ लाने की ज़रूरत है। मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में किसान आंदोलन से सीखकर, एक फासिस्ट–विरोधी और कारपोरेट–विरोधी जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है।

अभी 11 दिसंबर के बाद, हमारे पंजाब के कुछ संगठनों ने सोचा है कि पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें अपना हाथ आजमायेंगे। उन्हें लगता है कि वे पावर में आ जाएंगे। मेरी सोच है कि यह रास्ता ठीक नहीं है। हमारा काम था बचे हुए जो मुद्दे हैं, उसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करना, न कि एक छोटे मुद्दे के लिए, पंजाब के विधानसभा में एक सीट या कुछ सीटें लेना। अभी आंदोलन के सामने, किसान नेताओं के सामने, किसान संगठनों के सामने बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिये। हम 15 जनवरी की मीटिंग में प्लान करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, 13–14 राज्यों में बन गया है, और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी बनेगा। किसानों के जो मुद्दे हैं, वे इस आंदोलन में उठे मुद्दों से भी बड़े हैं। कुछ अनुभव किसानों और मज़दूरों के एक साथ संयुक्त कार्यवाही करने का हुआ है, उसे आगे कैसे बढ़ाना है, ये सब काम किसान आंदोलन के सामने हैं। किसान नेताओं को चाहिए था कि उसकी पूर्ति के लिए, एक संघर्षशील आंदोलन की पूर्ति के लिए, खुद को पेश करें, पंजाब असेंबली में जाने की कोशिश नहीं करें। यह रास्ता ठीक नहीं है।

मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत सारी सकारात्मक चीजों के अलावा, 26 जनवरी वाली, लाल किले वाली घटना से सरकार ने भटकाव पैदा करने की कोशिश की। फिर इन्होंने एक बेअदबी को लेकर हादसा करवाया, निहंग सिखों ने किसी मज़दूर को वहां मार दिया था, वह एक तरह की हमारे अंदर बंटवारा करने की कोशिश थी। फिर लखीमपुर खीरी की घटना, आशीष मिश्रा टैनी के बेटे ने 4 किसानों को गाड़ी से रौंद दिया, उसने इस तरह से दमन करने की कोशिश की। लेकिन हमारे किसान साथियों ने एकता और एक समझ के साथ कई चीजों को एक साथ हैंडल किया। केन्द्र सरकार की एजेंसियों की तरफ से हमें बिखेरने की, अंदर से तोड़ने की, हमें बदनाम करने की जो भी कोशिश की गयी, उसका मुक़ाबला करते–करते हमने केंद्र सरकार के साथ लड़ाई लड़ी। यहां तक कि जिस बोर्डर पर हम बैठे थे, स्थानीय गांव के लोगों के बीच हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गयी। लेकिन आंदोलन कुछ इस तरह का था कि ज्यादातर लोग यह कहते थे कि हम आंदोलनकारियों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। बेशक, हमें कुछ मुश्किलें आई हैं। हम उसको झेलेंगे। क्योंकि पहले दिन से ही वहां पर पानी का प्रबंध, रहने के लिए, उनको अपना वॉशरूम देने के लिए, हरियाणवी लोग आगे आए थे। लेकिन सरकार की एजेंसी फेल हुई। उन्होंने 27–28 जनवरी (2021 संपादक) को आर.एस.एस. के लोगों को लाकर स्टेज पर हमला करने की कोशिश की थी, डायरेक्टली पलवल बॉर्डर पर चल रहे धरना को जबरदस्ती उठा भी दिया। फिर 28 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा करने वाले थे, तब पंजाबी सिख किसान नौजवानों ने उस समय टिकैत जी को हौसला दिया कि हम खड़े हैं कुर्बानी देंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहां से हटेंगे नहीं। उस समय वह घटना घटी, जब टिकैत जी ने भावुक होकर अपील की। तो इन चीजों का सामना करते हुए, आंदोलन अंत में, एक हद तक पहुंचा, और तीन क़ानूनों को वापस किया। कुछ मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों को लेकर 15 जनवरी को हम अपनी समीक्षा करेंगे। आगे क्या करना है, उसके बारे में फ़ैसला करेंगे।

http://hindi.cgpi.org/21788

# मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Feb, 2022 Date of publish - 1 Feb, 2022


To .....

.....

.....

.....

.....

.....


स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

**अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :**

**ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020**

WhatsApp 9868811998


# आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं ने विरोध प्रदर्शन किया

31 जनवरी, 2022 को डेल्ही स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन (डी.एस.ए.डब्ल्यू.एच.यू.) के झंडे तले हजारों आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके पहले उसी दिन उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी की सरकार के ख़िलाफ़ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। हड़ताल के पहले दिन शहर के आंगनवाड़ी केन्द्रों के लगभग 70 प्रतिशत में काम का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया।

इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवेलपमेंट सर्विसेज़ (आई.सी.डी.एस.) आंगनवाड़ी योजना के तहत सरकार बच्चों की दिन में देखभाल के लिये 10,000 से भी अधिक केन्द्र चलाती है, इन केंद्रों पर दिल्ली के एक लाख से भी अधिक बच्चों व महिलाओं की देखभाल की जाती है। इन केन्द्रों को 22,000 आंगनवाड़ी मज़दूर व सहायिकायें चलाती हैं।

हड़ताल कर रही मज़दूरों और सहायिकाओं ने ध्यान दिलाया कि आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी होने के कारण उनके मानदेय में दिल्ली सरकार ने पिछली वृद्धि 2017 में की थी। उस वक्त भी उन्हें 58 दिनों के लिये हड़ताल

करनी पड़ी थी। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में उनका कार्यभार बढ़ गया है। परन्तु महंगाई और कार्यभार के बढ़ने के साथ, शहर की इस केवल–महिला श्रमशक्ति के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

प्रदर्शनकारियों ने केन्द्र सरकार की भी आलोचना की कि उसने 2018 में देशभर की आंगनवाड़ी मज़दूरों व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की थी लेकिन इसका भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया।

यूनियन ने बार–बार इन मांगों को उठाया है परन्तु सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की है। पिछले सितंबर, डी.एस.ए.डब्ल्यू.एच.यू. के नेतृत्व में दिल्ली सचिवालय पर एक चेतावनी विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद इस वर्ष जनवरी में एक दिन की हड़ताल की गयी।

आंगनवाड़ी मज़दूरों व सहायिकाओं की मुख्य मांगों में शामिल हैं – उनके मानदेय को क्रमशः 25,000 रुपये किया जाये और अक्तूबर 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मानदेय में वृद्धि का पिछले 39 महीनों के बकाये का भुगतान किया जाये। वर्तमान में दिल्ली में आंगनवाड़ी मज़दूरों व सहायिकाओं को क्रमशः 9,698 रुपये और 4839 रुपये मिलने चाहिये, जबकि उन्हें अभी तक "कर्मचारी" का दर्ज़ा नहीं दिया गया है। इस आंदोलन का अयोजन करने वाली यूनियन डी.एस.ए.डब्ल्यू.एच.यू. ने आंगनवाड़ी कर्मियों के लिये सेवानिवृत्ति की सुविधा तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) व भविष्य निधि (पी.एफ.) की मांग भी उठाई है।

पूरे देश के आंगनवाड़ी मज़दूरों की परिस्थिति इसी तरह की है, जबकि वे अपनी मांगों को लगातार हर एक राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उठाती आयी हैं। उनको सरकारी कर्मचारी बतौर मान्यता नहीं दी गयी है और राज्य सरकारों के वेतनमानों के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है। उन्हें मानदेय दिया जाता है जो देशभर के सबसे कम न्यूनतम वेतन से भी कम है और उन्हें सेवानिवृत्ति भत्तों से भी वंचित रखा गया है।

आंदोलित महिलाओं को संबोधित करते हुये डी.एस.ए.डब्ल्यू.एच.यू. के अध्यक्षा ने कहा कि "आने वाले नगर निगम चुनावों में हम उन पार्टियों का सक्रियता से बहिष्कार करेंगे जो हमारी मांगों की समय सीमा में पूर्ति का लिखित वादा नहीं करते"।

http://hindi.cgpi.org/21800

## सी.ई.एल. के मज़दूरों का संघर्ष

पृष्ठ 1 का शेष

सितंबर 2018 में बोलियां आमंत्रित की गई थीं, तब यह उल्लेख किया गया था कि बोली लगाने वाले को कम से कम पांच साल तक कंपनी के कारोबार को पूरी तरह से जारी रखना होगा। यह शर्त भी रखी गयी थी कि बोली लगाने वाली कंपनी एक मुनाफ़ा बनाने वाली कंपनी होगी – उसको दिखाना होगा कि उसने पिछले पांच वर्षों में कितना लाभ अर्जित किया है। 2021 में इन शर्तों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। हक़ीक़त में इसका मतलब यह है कि इस तरह के व्यवसाय को चलाने के किसी भी अनुभव के बिना, केवल कंपनी की महंगी ज़मीन और मशीनरी को ख़रीदने के लिए कोई भी बोली लगा सकता है

और इस ज़मीन का उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए भी कर सकता है।

सरकार की सी.ई.एल. का निजीकरण करने की योजना, राष्ट्र–विरोधी, जन–विरोधी और मज़दूर–विरोधी है। यह शासक पूंजीपति वर्ग के एजेंडे का एक हिस्सा है जो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के माध्यम से खुद को और भी अमीर बनाना चाहता है।

सी.ई.एल. के मज़दूर फिलहाल अपनी कंपनी को एक निजी कंपनी, नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग के हाथों में बिकने से रोकने में सफल रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सरकार ने इस कंपनी को निजी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने के अपने इरादे को वापस नहीं लिया है। 2021–22 के बजट में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ मुट्ठीभर कंपनियों को छोड़कर, बाकी सभी कंपनियों के निजीकरण के अपने फ़ैसले की घोषणा की थी। ये फ़ैसला सरकार ने अभी भी बदला नहीं है। सी.ई.एल. का निजीकरण सरकार के एजेंडे में शामिल है।

सी.ई.एल. के मज़दूरों को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और निजीकरण के ख़िलाफ़ अपना संघर्ष और भी तेज़ करना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/21806


### चुनाव पर हिन्दोस्तान की ग़दर पार्टी के कुछ प्रकाशन

**दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले जनवरी 2015 में प्रकाशित इस पुस्तिका में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार है**

**2014 लोक सभा चुनाव पर जारी किया गया हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का घोषणा पत्र**

### मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

**आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।**

**खाता नाम**–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**, न्यू दिल्ली, कालका जी
**खाता संख्या**–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810187911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com